मुद्रक : नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस)
नया बाजार, दिल्ली-६

भारतीय जनसंघ

प्रस्ताव

- श्रद्धांजलि
- किसान विरोधी बजट
- चुनाव और चुनाव-पद्धति में सुधार
- स्थायी शान्ति-समझौता आवश्यक

भारतीय कार्यसमिति
१८-१९ मार्च, १९७२, नई दिल्ली

श्रद्धांजलि

भारतीय कार्यसमिति श्री बच्छराज जी व्यास के आकस्मिक देहावसान पर गहरा शोक प्रकट करती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें तथा शोक-संतप्त परिवार को इस वज्राघात को सहन करने की शक्ति दें।

स्वर्गीय श्री बच्छराजजी व्यास भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के पद पर रहे थे और इन पदों का दायित्व उन्होंने बड़े उत्साह तथा निष्ठा के साथ सम्हाला। उनकी लोकसंग्रह वृत्ति, उनका स्नेहपूर्ण स्वभाव, समाज के प्रति उनकी समर्पण की भावना, राष्ट्र कार्य के लिए उनकी अटूट लगन और परिश्रमशीलता—कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण श्री बच्छराज व्यास संगठन के अत्यधिक उपयोगी और लोकप्रिय कार्यकर्ता थे। जीवन के अन्तिम क्षण तक वह राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में लगे रहे। उनके निधन से एक प्रखर राष्ट्रभक्त, निःस्वार्थ समाजसेवी तथा कुशल संगठनकर्ता हमारे बीच से उठ गया।

भारतीय कार्यसमिति देश तथा दल के लिए श्री बच्छराज जी व्यास की सेवाओं की सराहना करती है और उनके परिवार को आश्वासन दिलाती है कि इस शोक की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं।

किसान विरोधी बजट

१९७२-७३ का बजट किसान-विरोधी बजट है। इससे उन आश्वासनों का भी खोखलापन सिद्ध हो गया है जो भारतीय जनता को बेकारी के निराकरण मूल्यों की स्थिरता तथा आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बन की प्राप्ति के सम्बन्ध में दिये गए थे।

उर्वरकों, विद्युत चालित पम्पों तथा मशीन-तेल पर लगाये गए करों, जिसके साथ रहस्यपूर्ण ढंग से हाल में बढ़ाई गई ट्रैक्टरों की कीमत भी जुड़ी

हुई है, का अर्थ यह होगा कि खेती के आधुनिक तरीके अपनाना अधिक मंहगा हो जाएगा और इस प्रकार छोटे किसानों के लिए हरित क्रान्ति के लाभ में साझीदार बनने का मार्ग रोक दिया जाएगा।

इसके साथ ही खाद्यान्नों की खरीद में सरकार जो आर्थिक सहायता देती थी, वह घटाई जा रही है। कुल मिलाकर इन सभी कदमों से परिणाम यह होगा कि उपभोक्ता के लिए मूल्य बढ़ जाएँगे जबकि कृषि उत्पादक को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

मिट्टी के तेल में वृद्धि एक काला कदम है। यह निर्धन की रोशनी और रसोई घर की आग पर कर है। भारतीय इस्पात विश्व में पहले ही सबसे महंगा है। इस्पात पर भारी उत्पादन शुल्क लगाने का अर्थ यह होगा कि हर वस्तु—सुई से लेकर रेलवे इंजिन तक का दाम बढ़ेगा। इससे विशेषतः बुनियादी उद्योगों को क्षति पहुंचेगी और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात को ठेस लगेगी। इस्पात का मूल्य बढ़ने से मकानों, पुलों तथा कारखानों के निर्माण की लागत भी बढ़ेगी।

एल्यूमुनियम पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से न केवल गरीब के भोजन के बर्तन ही महंगे होंगे किन्तु इससे भी मूल उद्योगों विशेषतः हवाई जहाज निर्माण तथा केबल बनाने के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

सोडावाटर पर कर एक ऐसा कर है जो आम आदमी की एकमात्र विलास की वस्तु पर लगाया गया है।

इस बजट में अतिरिक्त करों का भार १८३ करोड़ रुपए नहीं है जैसाकि श्री चह्वाण ने दावा किया है, अपितु ५६५ करोड़ रुपए हैं, जिसमें गत वर्ष लगाए गए कर-भार शामिल हैं और जो इसी वर्ष पूरी तरह वसूल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त २४२ करोड़ रुपए का घाटा छोड़ा गया है।

पूर्व बंगाल के विस्थापितों के नाम पर लगाये गये करों को जारी रखने का अब कोई औचित्य नहीं है क्योंकि विस्थापित अपने घरों को वापस जा चुके हैं। बजट प्रस्तावों से जिसके साथ रेलवे-बजट में माल-भाड़े की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव भी शामिल है, कुल मिलाकर परिणाम यह होगा कि देश में ८ प्रतिशत से अधिक मूल्य वृद्धि हो जाएगी। इस वृद्धि से और गत वर्ष मूल्यों में भारी वृद्धि पहले ही हो चुकी है, मूल्य-मजूरी-वृद्धि का एक भारी चक्र चलेगा, जिससे आम आदमी की दशा और भी बिगड़ेगी।

इस बजट में योजना के अन्तर्गत व्यय की जो प्राथमिकताएं प्रस्तावित हैं वह पहले जैसी ही है। यह स्पष्ट है कि इन प्राथमिकताओं के कारण गत २० वर्षों में भारी बेकारी तथा मुद्रास्फीति बढ़ी है। इन प्राथमिकताओं को बनाये रखना यह बताता है कि सरकार को बढ़ती हुई बेकारी की जरा भी चिन्ता नहीं है। बेकारी में कमी करने के लिए इस बजट में कोई नया, निर्भीक तथा मूलगामी कार्यक्रम नहीं है, जो सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए आश्वासनों के विपरीत है।

सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए १५५ करोड़ रुपए की धनराशि सर्वथा अपर्याप्त है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं को स्पर्श भी नहीं किया जा सकेगा। हरिजन, वनवासियों तथा पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। बजट जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के राष्ट्रीय सामाजिक उद्देश्यों से पूर्णतः रहित है।

१९७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सत्तारूढ़ दल ने स्वावलम्बन का जो जोशपूर्ण आह्वान दिया था उसे भी सुविधाजनक ढंग से भुला दिया गया है। इस वर्ष विदेशी सहायता की जो मात्रा की जा रही है वह गत वर्ष में मिली विदेशी सहायता से ७५ करोड़ रुपए अधिक है। भारतीय जनसंघ एक स्वाव-लम्बी अर्थ-व्यवस्था की अपनी मांग को दोहराता है।

बजट गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में कटौती करने के बारे में सरकार की जागरूकता का कोई परिचय नहीं देता। इसके विपरीत सरकारी खर्च में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अनुमान ५ प्रतिशत का था। यदि सरकार फिजूलखर्ची को रोकने और ऊंचे स्थान पर विलास पर होने वाले व्यय में कमी का कोई उदाहरण नहीं रख सकती तो वह ऐसा वातावरण नहीं बना सकती जिसमें लोग भविष्य के लिए बचत करें।

जनसंघ मांग करता है कि :—

(१) गत वर्ष विस्थापितों के नाम पर जो अतिरिक्त कर तथा अधिभार लगाया गया था उनको समाप्त किया जाए;

(२) मिट्टी के तेल, उर्वरक, पम्पों तथा मशीन के तेल पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क वापस लिया जाय;

(३) इस्पात तथा एल्यूमिनियम पर लगे शुल्क में भारी कमी की जाय;

(४) प्रत्यक्ष कर प्रणाली का पुनर्निर्धारण किया जाय जिससे आय-कर की

न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर कम आय वालों को राहत दी जा सके और उच्चस्तर पर आय-कर की दर में कमी हो, जिससे करों की चोरी रुके;

(५) सार्वजनिक निर्माण का एक विशाल कार्यक्रम बनाया जाय जिससे बेरोजगारी दूर की जा सके और भवन निर्माण, पेय जल का प्रबन्ध, गन्दी बस्तियों की सफाई, शिक्षा तथा पिछड़े वर्गों को उठाने की ठोस परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाय ।

चुनाव और चुनाव-पद्धति में सुधार

भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटने, विरोधी दलों को समाप्त करने और शासन तंत्र के निर्लज्ज दुरुपयोग तथा धनबल के आधार पर चुनावों को एक निरर्थक तमाशा बनाने के सुनिश्चित प्रयत्न को गंभीर चिन्ता की दृष्टि से देखती है।

भारतीय जनसंघ का मत है कि हाल में ही जो विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए हैं उनमें एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल के साथ संघर्ष नहीं हुआ बल्कि गैर कांग्रेसी दलों को, अलग-अलग रूप से, सरकार के साथ लड़ना पड़ा। जिन कठिनाइयों के बीच जनसंघ तथा अन्य दलों को संघर्ष करना पड़ा, उन्हें देखते हुए कांग्रेस की विजय को सर्वथा आश्चर्यजनक नहीं माना जा सकता ।

भारतीय जनसंघ ने इन चुनावों को राज्य स्तर के प्रश्नों पर लड़ने का निर्णय किया था । किन्तु बांगला देश की विजय की पृष्ठभूमि में श्रीमती गांधी की प्रतिभा को योजनाबद्ध रीति तथा प्रबल रूप से पेश कर सरकारी पार्टी वास्तविक प्रश्नों के सम्बन्ध में जनता को भ्रम में डालने और इस प्रकार विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव को पृथक करने के एकमेव औचित्य को ही व्यर्थ करने में सफल हो गई।

फिर भी बांगला देश के निर्माण का लाभ उठाने का नग्न प्रयत्न सरकारी कांग्रेस को इतनी विजय दिलाने का कारण नहीं बनता जितनी विजय उसे मिली है । इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तथा धनशक्ति का उपयोग उतने पैमाने पर किया गया जितना आज तक कभी नहीं हुआ । सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच की विभाजक रेखा लगभग समाप्त

कर दी गई थी । कुछ राज्यों में दिल्ली की भांति, पुलिस तथा गुप्तचर विभाग को सक्रिय रूप से चुनाव अभियान में शामिल किया गया । इन कारणों से चुनावों को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता । कुछ अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर हिंसा, भय तथा आतंक की वजह से मतदाताओं के लिए स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करना असंभव हो गया ।

दिल्ली में जनसंघ को श्रीमती इन्दिरा गांधी से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री तथा उनके इशारे पर चलने वाले भारी सरकारी साधनों से लड़ना पड़ा । यदि इसके बावजूद जनसंघ न केवल अपने जनसमर्थन में वृद्धि करने में सफल हुआ है, बल्कि उन सभी महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्रों को अपने पास रखने में कामयाब हुआ है जिनमें प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी, तो यह राजधानी में जनसंघ द्वारा किए गये कामों की सराहना तथा उसके प्रतिनिधियों द्वारा अर्जित आदर का ही प्रतीक है ।

सन् १९५१ के बाद से चुनाव निरन्तर मंहगे होते जा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में चुनाव में पूंजी का प्रयोग कई गुणा बढ़ गया है । गत विधानसभा चुनावों में कुल मिलाकर जो धन खर्च किया गया वह अब तक के चुनावों में व्यय धनराशि से कई गुना अधिक होगा । चुनाव-व्यय पर मर्यादा लगाने का कानून एक मजाक बन गया है । चुनाव कानून संशोधन के लिए बनी संसदीय समिति ने ठीक ही सिफारिश की है कि "उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल द्वारा जो उचित चुनाव व्यय किया जाता है उसे उत्तरोत्तर राज्य के ऊपर डाला जाना चाहिए ।" इसके साथ ही चुनाव में बढ़ती हुई हिंसा तथा शासन-तन्त्र के दुरुपयोग ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें चुनाव न तो निष्पक्ष हो सकते हैं और न स्वतंत्र ।

भारतीय जनसंघ अनुभव करता है कि यद्यपि भारत में ५ महानिर्वाचन हो चुके हैं और आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि चुनाव अधिकाधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं, इस बात का अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है कि इस दुरावस्था को रोका जाय । चुनाव आयोग ने समय-समय पर चुनाव कानून में यहां-वहां थोड़ा बहुत हेर-फेर करने का प्रयत्न किया है, किन्तु अनेक बार यह प्रयास रोग को ठीक करने के बजाय उसे और अधिक बढ़ाने में ही कारणीभूत हुआ है । सचाई यह है कि अब तक चुनावों में मूलगामी सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । वस्तुतः चुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में ही पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत किसी दल को विधान-

सभा में प्राप्त स्थानों का उस दल को मिले व्यापक जनसमर्थन से बहुधा कोई सम्बन्ध नहीं होता।

भारतीय कार्यसमिति तीव्रता से अनुभव करती है कि चुनाव-पद्धति, तथा कानून में सुधार के मामले में अब और अधिक देर नहीं की जानी चाहिए। सभी लोकतंत्रवादियों को, फिर वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों, इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसे तौर-तरीके ढूंढना चाहिए जिससे वर्तमान चुनावतंत्र जनता की इच्छा को प्रामाणिकतापूर्वक प्रतिबिम्बित कर सके। भारतीय जनसंघ संकल्प करता है कि वह चुनाव में भ्रष्टाचार तथा धांधलियों के विरुद्ध चुनाव पद्धति में सुधार के लिए सतत संघर्ष करेगा। भारतीय कार्यसमिति दल के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अधिकार देती है कि अन्य दलों के नेताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक पग उठायें।

स्थायी शान्ति समझौता आवश्यक

जब से पाकिस्तान के साथ १४ दिवसीय युद्ध समाप्त हुआ है, भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि वह इस बात की चिंता किये बिना कि दोनों देशों के बीच एक सर्वस्पर्शी शान्ति समझौता होता है या नहीं और अन्य सभी प्रमुख विवाद हल किए जाते हैं या नहीं, पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को लौटा दे और पाकिस्तानी भूमि को खाली कर दे। राष्ट्रपति भुट्टो द्वारा बारी-बारी से मीठी तथा कड़वी बातें करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि उनके सिपाही जल्दी से जल्दी वापस आ जायें।

अब यह पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि चीन ने पाकिस्तान का पूरा साथ देने का निर्णय कर लिया है। निक्सन शासन भी पाकिस्तान का खुला साथ दे रहा है। सोवियत रूस भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यवर्ती स्थिति की ओर बढ़ता दिखाई देता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (दक्षिणपंथी) द्वारा पारित यह प्रस्ताव कि भारतीय सेनाएं सन् १९४८ की युद्धविराम रेखा पर वापस लौट जायें, मास्को के मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब माना जा सकता है। भारत सरकार के प्रवक्ताओं ने अभी से यह कहना आरंभ कर दिया है कि कश्मीर में युद्धविराम रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लिया जाय। इसका अर्थ भारत की ३० हजार वर्गमील जमीन को हमेशा के लिए त्याग देना होगा। यह भारत की सार्वभौमता तथा

अखंडता के साथ विश्वासघात होगा।

राष्ट्रपति भुट्टो श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ सीधी वार्ता की बातें कर रहे हैं। यद्यपि इस आशय के वक्तव्य दिये जा रहे हैं, किन्तु इस दिशा में न तो कोई कूटनीतिक कदम उठाये गए हैं और न प्रस्तावित शिखर-सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कोई प्रारंभिक कार्रवाई की गई है। स्पष्टतः श्री भुट्टो की ये घोषणायें अन्तर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित करने के लिए हैं।

भारतीय जनसंघ पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता का विरोधी नहीं है, फिर चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, बशर्ते कि भारत सरकार पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दे कि यह वार्ता पाक युद्धबंदियों के प्रश्न, जो बंगला देश की सरकार से भी जुड़ा हुआ है, तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान से सम्बन्धित सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, यथा—पाक अधिकृत कश्मीर, युद्ध के लिए क्षतिपूर्ति, सिंध के थरपारकर जिले के हिन्दू निवासी, पाकिस्तान द्वारा अब तक न चुकाये गए ऋण, जिनमें विस्थापितों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति शामिल है, आदि। ऐसा कोई समझौता जो उन्हीं मुद्दों को स्पर्श करता है जो पाकिस्तान के लिए लाभदायक है, गलत, अदूरदर्शी और राष्ट्रीय हितों के विपरीत होगा। जब तक सभी विवाद हल नहीं होते, और स्थायी शान्ति की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक भारतीय सेनाओं को वापस बुलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए।

इस सप्ताह के आरंभ में मास्को ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा है। स्पष्टतः दूसरे ताशकन्द की तैयारी हो रही है। भारतीय कार्यसमिति भारत सरकार को अपने इस वचन का स्मरण दिलाना चाहेगी कि इस बार दूसरा ताशकन्द नहीं होगा। भारतीय जनसंघ की मांग है कि सरकार अपने वचन का पालन करे और सोवियत रूस को साफ-साफ कह दे कि वह १९६६ की पुनरावृत्ति के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता निश्चित रूप से यह नहीं होने देगी।

भारतीय कार्यसमिति को आशंका है कि यदि श्री भुट्टो अपनी शर्तों पर युद्धबंदियों की रिहाई नहीं करा पाते तो पाकिस्तान तथा उसके साथी देश इस भूखंड की शांति को पुनः भंग करने के दुस्साहस से भी बाज नहीं आयेंगे। उस स्थिति में जम्मू-कश्मीर पाकिस्तानी शरारत का मुख्य लक्ष्य होगा। लाऊ-निक्सन विज्ञप्ति में तथा श्री भुट्टो द्वारा कुछ भारतीय पत्रकारों को दी

गई भेंटवार्ता में कश्मीर की रट लगाना इस दिशा में गंभीर खतरे के संकेत हैं। भारत को सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारतीय कार्यसमिति सभी जनसंघ शाखाओं को निर्देश देती है कि वह उपर्युक्त प्रश्न पर प्रभावी रूप से जनमत का संगठन करें।